multidisciplinery team of scientific/technical personnel alongwith Animal Scientist. The activities related to livestock production and management are taken up within the overall need of the farming system prevailing in the area.

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति के प्रतिनिधि मंडल की ओर से अभ्यावेदन

739. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र, लाहौल स्फीति जिले का एक प्रतिनिधि मंडल हाप्स उत्पादनों की समस्याओं के संबंध में गत सत्र के दौरान उनसे मिला था और उन्हें एक लिखित ज्ञापन भी दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं। तथापि, प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री जी से मिला था तथा उसने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे अलग-अलग विभागों के क्षेत्र में आते हैं और इस मामले पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ बातचीत की गई है।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

740. **श्री राम गोपाल यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने की नीतिगत फैसला कर लिया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो इसकी प्रति बोरी दर क्या होगी तथा यह बढ़ी हुई दर कब से लागू होगी और मध्यम तथा निम्न वर्ग के किसानों पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार उर्वरकों पर दी जा रही राज सहायता समाप्त कर रही है/कम कर रही है। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो मूल्य वृद्धि का क्या औचित्य है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां। यूरिया के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ताकि एनपीके पोषकों के उपयोग में असंतुलन को कम किया जा सके। फॉस्फेटिक, पोटाशिक एवं निम्न विश्लेषण नाइट्रोजेन्स उर्वरकों के मूल्यों को पहले ही विनियंत्रित किया जा चुका है।

(ख) यूरिया के मूल्य में वृद्धि 21.2.97 से प्रभावी होगी तथा संशोधित मूल्य 183/- रु० प्रति 50 कि०ग्रा० थैला है (3660 रु० प्रति टन)। यह वृद्धि मध्यम, छोटे एवं सीमान्त सहित सभी वर्ग के किसानों पर लागू होगी।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार यूरिया पर राजसहायता के अलावा किसानों को फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत दे रही है।

Industrial Units for Production of Milk Powder and Ghee

741. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) the names and locations of large scale industrial units set-up for preparing milk powder and ghee from milk;

(b) the capacity of these units and expenditure incurred on their setting-up; and

(c) whether Government propose to set-up such units in all the States to meet the shortage of milk and ghee?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) and (b) most of the units are not owned by the Government and hence details regarding the expenditure incurred in their setting up are not available. The information regarding the names and locations of the units is being compiled.

(c) Government have financed the setting up of such units in most of the states through the Operation Flood Programme.

Central Schemes for Development of Animal Husbandry and Dairying in Rajasthan

742. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of ANIIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) the details of various Central schemes being implemented in Rajasthan

for the development of animal husbandry and dairy;

(b) the amount allocated during 1995-96, 1996-97 and 1997-98, year-wise and scheme-wise; and

(c) the targets fixed and achievements made year-wise so far, scheme-wise, for the above mentioned period?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) The details of central schemes, being implemented by the Department of Animal Husbandry and Dairying for supplementing the efforts of the State Governments including the State of Rajasthan for the development of animal husbandry and dairy are indicated in the statement enclosed.

(b) Separate state-wise allocations are not earmarked under these schemes. The central assistance is provided to the State Governments on the basis of viable proposals received from them. The central assistance provided to Government of Rajasthan during 1995-96 and 1996-97 are indicated in the Statement enclosed (see below)'.

(c) The main objective of these schemes is to enhance the productivity levels of livestock to increase the production of major livestock products, viz. milk, egg, wool, etc. The target and achievement in respect of these products are given below:

	1995-96		1996-97		1997-98
	Target	likely achie-vement	Target	Achie-vement	Target
1. Milk Production (Lakh Tonnes)	52.0	52.0	53.5	53.5	55.0
2. Egg. Production (Million Nos.)	400.0	450.0	475.0	475.0	500.0
3. Wool Production (Million Kgs.)	18.0	17.7	18.0	18.0	18.3

Statement

The Central Assistance Provided to whether of Rajasthan Under Various Central Plan Government Schemes During 1995-96 and 1996-97 upto December, 1996.

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Scheme	Funds released during		
		1995-96	1996-97	1997-98
1.	Extension frozen Semen technology and Progency Testing Programme	—	—	Statewise allocations are not earmarked
2.	National Bull Prod. Prog.	—	—	
3.	National Ram/Buck Production Programme	10.00	—	
4.	Integrated Piggery Development Programme	2.25	—	

1	2	3	4	5
5.	Preservation and Development of Pack Animals	1.25	—	
6.	National Project on rnderpest Eradication Programme	19.49	24.69	
7.	Assistance to States for control of Animal Diseases			
	(i) Systematic control of Livestock Diseases	14.39	16.68	
(ii)	Foot and Mouth Disease Control Programme	50.00	—	
(iii)	Animal Disease Surveillance	2.45	—	
8.	Professional Efficiency Dev.	2.45	0.40	
9.	Assistance to States for Feed and Fodder Development	—	—	
		—	—	
10.	Assistance to States for improvement/ Modernisation of Slaughter Houses/ Carcass Utilisation Centre	—	—	
11.	Integrated Sample Survey	16.50	15.00	
12.	Animal husbandry Extension Programme	—	3.00	
13.	Special Livestock development Programme	—	—	
14.	Integrated Dairy Development Programme	—	—	

"इण्डिया सैट टु बिकम नं० वन मिल्क प्रोड्यूसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

743. **श्री राम जेठमलानी:** क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इंडिया सैट टु बिकम नं० वन मिल्क प्रोड्यूसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और भारत में इस समय कितना दूध उत्पादन हो रहा है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि अब भी दूध का प्रति व्यक्ति उपभोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना में कम है; यदि हां, तो दूध के लिए निर्धारित मानदण्ड एवं उसके उपभोग में कितना अंतर है?

कृषि मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और वर्ष 1998-99 तक इसके पहले स्थान पर आ जाने की संभावना है। अंतरिम अनुमानों के अनुसार, 1995-96 के दौरान दूध का उत्पादन 66 मिलियन टन था और 1996-97 में प्रत्याशित उत्पादन 69 मिलियन टन है।

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1993-94) के 50वें दौर के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत लगभग 134 ग्राम है तथा शहरी क्षेत्रों में 149 ग्राम जबकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दूध की प्रति व्यक्ति/दिन 220 ग्राम मात्रा की सिफारिश की है।